[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India  
Ministry of Corporate Affairs  
Notification  
New Delhi, the ___ February, 2020

G.S.R. ___ (E).- In exercise of the powers conferred by section 41 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Issue of Global Depository Receipts) Rules, 2014, namely:

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Issue of Global Depository Receipts) Amendment Rules, 2020.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Issue of Global Depository Receipts) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

   (i) for the words, brackets and figures "Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993" at both the places where they occur, the words and figures "Depository Receipts Scheme, 2014" shall be substituted;

   (ii) in sub-rule (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
       ‘(aa) "overseas depository" or "overseas depository bank" shall mean ‘foreign depository' as defined in the Scheme.’.

3. In the said rules, in rule 5,-

   (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
       “(1) The depository receipts can be issued by way of public offering or private placement or in any other manner prevalent in the concerned jurisdiction and may be listed or traded on the listing or trading platform in the concerned jurisdiction.”;
(ii) in sub-rule (3), the word "abroad" shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 7, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that proceeds of issue of depository receipts may be remitted in an International Financial Services Centre Banking Unit (IBU) and utilised in accordance with the instructions issued by the Reserve Bank of India from time to time."

5. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), the word "abroad" shall be omitted.

[File No. 1/21/2013-CL-V-part]

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 252(E), dated the 31st March, 2014.
[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कार्यपोर्ट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ......13 फरवरी, 2020

सा.का.नि. ...............(अ)।- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)
की धारा 469 के साथ पत्ता धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी
(वैश्विक निकेशपागार प्राप्तियों का निर्माण) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (वैश्विक निकेशपागार
प्राप्तियों का निर्माण) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (वैश्विक निकेशपागार प्राप्तियों का निर्माण) नियम, 2014 (इसे इसमें इसके पश्चात्
उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में,-
(i) “विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड तथा साधारण शेयर (निकेशपागार प्राप्ति तंत्र के
माध्यम से) स्कीम, 1993” शब्दों, कोषिकाओं और अंकों के लिए दोनों स्थानों पर जहाँ यो
आए हैं, “निकेशपागार प्राप्ति स्कीम, 2014” शब्द और अंक रखें जाएंगे;
(ii) उप-नियम (1) में, उपबंध (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया
जाएगा, अर्थात्:-

‘(कक) “विदेशी निकेशपागार” या “विदेशी निकेशपागार बैंक” का अभिप्राय ‘विदेशी
निकेशपागार’ होगा, जैसा कि स्कीम में परिभाषित है।

3. उक्त नियमों के, नियम 5 में,-
(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) निकेशपागार प्राप्तियाँ सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से या निजी प्लेसमेंट या
संबंधित अधिकारिता में प्रचलित किसी अन्य रीति से जारी की जा सकती हैं और
संबंधित अधिकारिता में सूचीबद्ध करते हुए या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध या व्यापार किया जा सकेगा।

(ii) उप-नियम (3) में, शब्दों "विदेश में" का विलोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के, नियम 7 में, निम्नलिखित परारंत अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातः
“परारंत निक्षेपकार प्राप्तियों के निर्माण के प्रतिफल किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) में प्रेषित किए जा सकेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार उपयोग किए जा सकेंगे।

5. उक्त नियमों के, नियम 9 के, उप-नियम (1) में, शब्दों "विदेश में" का विलोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/21/2013-सीएल-V (भाग)]

(के.वी.आर. मूलि)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 252(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।